

हड़ताल का अधिकार

प्रलिमिन्स के लिये:

अनुच्छेद 19, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मौलिक अधिकार।

मेन्स के लिये:

हड़ताल का अधिकार।

चर्चा में क्यों ?

केरल उच्च न्यायालय ने इस बात को दोहराया है कि जो सरकारी कर्मचारी हड़तालों में भाग लेते हैं तथा सरकारी खजाने के साथ-साथ सामान्य जनता के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, वे [संविधान के अनुच्छेद 19\(1\)\(c\)](#) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं, साथ ही यह केरल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1960 के प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन है।

हड़ताल का अधिकार:

■ परिचय:

- हड़ताल का आशय नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित आवश्यक शर्तों के तहत काम करने से **कर्मचारियों का सामूहिक रूप से इनकार** करना है। हड़ताल के कई कारण हो सकते हैं, हालाँकि **मुख्य तौर पर आर्थिक स्थितियों** (आर्थिक हड़ताल के रूप में परिभाषित और मजदूरी एवं लाभ में सुधार के लिये) या **श्रम प्रथाओं** (कार्य स्थितियों में सुधार के उद्देश्य से) के संदर्भ में की जाती है।
- प्रत्येक देश में चाहे वह लोकतांत्रिक हो, पूंजीवादी या समाजवादी हो श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिये लेकिन यह अधिकार अंतिम उपाय के रूप में उपयोग होना चाहिये क्योंकि यदि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाता है तो यह उद्योगों के उत्पादन और वित्तीय लाभ में समस्या उत्पन्न करेगा।
- यह अंततः देश की **अर्थव्यवस्था को प्रभावित** करेगा।
- भारत में वसिष्ठ का अधिकार भारतीय संविधान के [अनुच्छेद 19](#) के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- लेकिन **हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानूनी अधिकार** है और इस अधिकार के साथ **औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध** जुड़ा हुआ है।
 - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 को [औद्योगिक संबंध संहिता, 2020](#) के तहत समाहित किया गया है।

■ भारत में स्थिति:

- अमेरिका के विपरीत भारत में हड़ताल का अधिकार कानून द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है।
- वाणिज्यिक विवाद के समर्थन में **पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा की गई वशिष्ठ कार्रवाइयों को मंजूरी देकर**, जो अन्यथा सामान्य आर्थिक कानून का उल्लंघन कर सकती थी, ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 ने हड़ताल संबंधी पहला प्रतिबंधित अधिकार बनाया।
- वर्तमान में हड़ताल के अधिकार को **ट्रेड यूनियनों के एक वैध हथियार के रूप में कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के तहत सीमित मान्यता प्राप्त है।**
- भारतीय संविधान हड़ताल करने का पूर्ण अधिकार नहीं प्रदान करता, लेकिन यह संघ का गठन करने की मौलिक स्वतंत्रता का पालन करता है।
- **राज्य ट्रेड यूनियनों को संगठित करने और हड़तालों का आह्वान करने की क्षमता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है**, जैसा कि हर दूसरा मौलिक अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

■ अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत हड़ताल का अधिकार:

- हड़ताल के अधिकार को [अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन](#) (International Labour Organization- ILO) के सम्मेलनों द्वारा भी मान्यता दी गई है।
 - भारत ILO का संस्थापक सदस्य है।

हड़ताल के अधिकार से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण नरिणय:

- दल्लि पुलसि बनाम भारत संघ (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने पुलसि बल (अधिकारों का प्रतिबंध) अधिनियम, 1966 और संशोधन नियम, 1970

- द्वारा संशोधित नयिमों के प्रभावी होने के बाद गैर-राजपत्रित पुलिस बल के सदस्यों द्वारा संघ बनाने के प्रतर्द्धों को बरकरार रखा।
- टी. के. रंगराजन बनाम तमलिनाडु सरकार (2003) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कर्मचारियों को हड़ताल का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा उनके हड़ताल पर जाने पर तमलिनाडु सरकारी सेवक आचरण नियम, 1973 के तहत रोक है।

स्रोत: द हिंदू

21वीं सदी में वैश्विक हमिनद परिवर्तन

परलमिस के लिये: पेरसि जलवायु समझौता, वैश्विक हमिनद परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन

मेन्स के लिये: 21वीं सदी में वैश्विक हमिनद परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में “ग्लोबल ग्लेशियर चेंज इन द 21st सेंचुरी: एवरी इनक्रीज़ इन टेम्परेचर मैटर्स” शीर्षक वाली एक रपॉर्ट में कहा गया है कि पृथ्वी के आधे हमिनद वर्ष 2100 तक लुप्त हो सकते हैं।

- शोधकर्त्ताओं ने ग्रह के हमिनदों को पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ मापने के लिये दो दशकों के उपग्रह डेटा का उपयोग किया।
- [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र \(UN\) के अंतर-सरकारी पैनल की वर्ष 2022 में जारी छठी मूल्यांकन रपॉर्ट](#) में भी चेतावनी दी गई थी कि हमारे पास 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को हासिल करने के लिये समय कम है।

रपॉर्ट के मुख्य बंदि:

- **अभूतपूर्व दर से पघिल रहे हैं हमिनद:**
 - [जलवायु परिवर्तन](#) और बढ़ते तापमान के कारण [हमिनद](#) अभूतपूर्व दर से घट रहे हैं।
 - वर्ष 1994 से वर्ष 2017 के बीच हमिनदों से पघिली बर्फ की मात्रा लगभग 30 ट्रिलियन टन थी और अब वे प्रत्येक वर्ष 1.2 ट्रिलियन टन की गति से पघिल रहे हैं।
 - आल्प्स, आइसलैंड एवं अलास्का के ग्लेशियर उनमें से कुछ हैं जो सबसे तेज़ गति से पघिल रहे हैं।
 - पृथ्वी के आधे हमिनद वर्ष 2100 तक लुप्त हो जाएंगे, भले ही हम वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के [पेरसि जलवायु समझौते](#) के लक्ष्य का पालन करते रहें।
 - अगले 30 वर्षों के भीतर कम-से-कम 50% नुकसान होगा। यदि ग्लोबल वार्मिंग अपनी वर्तमान 2.7 डिग्री सेल्सियस दर पर बना रहता है तो 68% ग्लेशियर पघिल जाएंगे।
 - यदि ऐसा होता है, तो अगली सदी के अंत तक मध्य यूरोप, पश्चिमी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तव में कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा।
 - शोधकर्त्ताओं का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करके इनमें से कुछ ग्लेशियरों को पघिलने से बचाया जा सकता है।
 - ग्लेशियर, जिनमें पृथ्वी के ताज़े पानी का 70% हिस्सा मौजूद है, वर्तमान में यह पृथ्वी के भूमिक्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है।
- **आपदा के बढ़ते जोखिम:**
 - ग्लेशियर के पघिलने से समुद्र का स्तर बहुत बढ़ जाता है, जिससे दो अरब लोगों की पानी तक पहुँच प्रभावित हो सकती है और [प्राकृतिक आपदाओं](#) तथा बाढ़ जैसी [चरम जलवायु घटनाओं](#) की संभावना बढ़ जाती है।
 - वर्ष 2000 और 2019 के बीच वैश्विक समुद्र स्तर में 21% की वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों का पघिलना था।
- **अनुशंसाएँ:**
 - वैश्विक तापमान में 1.5C से अधिक की वृद्धि के साथ तेज़ी से बढ़ते ग्लेशियर एवं जन हानि पर प्रतीक क्षेत्रों में ग्लेशियरों को संरक्षित करने के लिये अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु प्रतर्जिआएँ करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न: जलवायु-स्मार्ट कृषि के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचिार कीजिये:

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम' दृष्टिकोण जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा (CCAFS) अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यक्रम के नेतृत्व में परियोजना का हिस्सा है।

2. CCAFS परियोजना अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह (CGIAR) के अधीन संचालित की जाती है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
3. भारत में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न: नमिनलखिति में से कौन भारत सरकार के 'हरति भारत मशिन' के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? (2016)

1. संघ और राज्य के बजट में पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को शामिल करना जिससे 'हरति लेखांकन' को लागू किया जा सके।
2. कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु दूसरी हरति क्रांति शुरू करना ताकि भविष्य में सभी के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
3. अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से वन आवरण को बहाल करना एवं बढ़ाना तथा जलवायु परिवर्तन का प्रत्युत्तर देना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न.3 'वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

1. यह यूरोपीय संघ की एक पहल है।
2. यह लक्षित विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के लिये तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
3. यह वैश्व संसाधन संस्थान (World Resources Institute) और सतत विकास के लिये वैश्व व्यापार परिषद (World Business Council for Sustainable Development) द्वारा समन्वित है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
(b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

[[[?/?/?/?/?]]]:

प्रश्न 1. जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न 2. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017)

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022

प्रलमिस के लयि:

दूरसंचार वभिग, भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022, पीएम गतशिक्ती NMP ।

मेन्स के लयि:

भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022 का महत्त्व ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार वभिग ने भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022 बनाया है ।

- एक मजबूत, सुरक्षित, सुलभ एवं **कफ़ायती डिजिटल संचार अवसंरचना** और सेवाओं के निर्माण के माध्यम से केंद्र सरकार ने व्यक्तियों तथा व्यवसायों दोनों की संचार संबंधी मांगों को पूरा करने की परकिल्पना की है ।

भारतीय टेलीग्राफ (अवसंरचना सुरक्षा) नयिम, 2022:

- कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी संपत्ति के उत्खनन या इसके कानूनी अधिकार का उपयोग करना चाहता है, जिससे दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान होने की आशंका है, उत्खनन शुरू करने से पहले सामान्य पोर्टल के माध्यम से लाइसेंसधारी को नोटिस देगा ।
- खुदाई या उत्खनन करने वाला व्यक्ति लाइसेंसधारी द्वारा उपलब्ध कराए गए एहतियाती उपायों के अनुसार उचित कार्रवाई करेगा ।
- कोई भी व्यक्ति जिसने दूरसंचार अवसंरचना को नुकसान पहुंचाने वाली किसी परसंपत्ति की खुदाई/उत्खनन का कार्य किया है, वह दूरसंचार प्राधिकरण को नुकसान शुल्क का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा ।
- एक बार परसंपत्ति स्वामित्व वाली एजेंसियों **पीएम गतशिक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान** मंच पर GIS निर्देशांक के साथ अपनी मौजूद परसंपत्तियों का मानचित्रण कर लेती है, तो इससे उत्खनन शुरू होने से पहले संबंधित स्थल पर मौजूद उपयोगी संपत्तियों के बारे में जानना संभव होगा ।

संबद्ध लाभ:

- कई उपयोगी संपत्तियों को अवांछित **कटौती और बहाली की दशा में अतिरिक्त लागत से बचाया जा** सकता है ।
 - नतीजतन, नगिम हज़ारों करोड़ रुपए की बचत कर पाएंगे, जबकि सरकार को कर का नुकसान होगा ।
- एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल से नागरिकों को होने वाली असुविधा का समाधान किया जा सकता है ।

प्रधानमंत्री गतशिक्ती-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP):

- उद्देश्य:**
 - ज़मीनी स्तर पर कार्य में तेज़ी लाने, लागत को कम करने और **रोज़गार सृजन** पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में **बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं** की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ।
 - लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य **कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों** पर टर्नअराउंड समय को कम करना ।
 - यह वर्ष **2024-25 के लिये सरकार द्वारा निर्धारित महत्त्वकांक्षी लक्ष्यों** को पूरा करने में मदद करेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई को 2 लाख किलोमीटर तक विस्तारित करना, **200 से अधिक नए हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण करना शामिल है ।**
- पीएम गतशिक्ती छह प्रमुख स्तंभों पर आधारित है:**
 - व्यापकता:** इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा व नयोजित पहलें शामिल होंगी । प्रत्येक विभाग अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना एवं निष्पादन करते समय महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता में रहेगा ।
 - प्राथमिकता:** इसके माध्यम से विभिन्न विभाग क्रॉस-सेक्टरल इंटरैक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे ।
 - अनुकूलन:** राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्त्वपूर्ण कमियों की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा । यह योजना माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिये समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग का चयन करने में मदद करेगा ।
 - तुल्यकाल (Synchronization):** अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलो (विभाग) में काम करते हैं । परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में समन्वय की कमी के परिणामस्वरूप देरी होती है । पीएम गतशिक्ती प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन के विभिन्न स्तरों के बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करने में मदद करेगा ।
 - वशिलेपण:** योजना GIS आधारित स्थानिक योजना और 200+ स्तरों वाली वशिलेपणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा

प्रदान करेगी, जिससे नषिपादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता मिल सकेगी।

- **डायनेमिक:** सभी मंत्रालय और विभाग अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी से समय-समय पर ज़मीनी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और परियोजनाओं की प्रगति को अपडेट किया जाएगा। पोर्टल पर नियमिit रूप से यह मास्टर प्लान को बढ़ाने तथा अद्यतन करने हेतु महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करेगा।

■ गतिशक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म:

- इसमें एक अम्बरेला प्लेटफॉर्म का निर्माण शामिल है, जिसके माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच वास्तविक समय पर समन्वय के माध्यम से बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
- यह अनिवार्य रूप से रेलवे और सड़क परिवहन सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म है।



**Pragati Ki Gati
Bharat Ki Shakti**

**Connecting
Pillars of
New India**

-  To cover infrastructure initiatives like Bharatmala, Sagarmala, Ports, UDAN, Economic Zones, Railways etc
-  Social infrastructure such as hospitals, universities to be integrated in the next phase
-  To develop new possibilities for the creation of future economic zones



**Pragati Ki Gati
Bharat Ki Shakti**

**Making India
the hub of
world-class
infra**

-  Comprehensive master plan mapping all existing/planned initiatives of Ministries
-  Guide the creation of economic zones & connectivity infrastructure
-  Help remove regional & sectoral imbalances in infrastructure & connectivity
-  Aid faster growth of key sectors, employment generation & spearheading growth

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. गति-शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये सरकार और नजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। वविचना कीजिये। (मेन्स-2022)

https://www.youtube.com/watch?v=lqIYW_4onJw

स्रोत: पी.आई.बी.

मानवरहति युद्ध प्रणाली और चतिारै

प्रलिमिस के लयि:

भारतीय नौसेना, हदि महासागर क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्र, कृत्रमि बुद्धमित्ता

मेन्स के लयि:

मानव रहति युद्ध प्रणाली और चतिारै, युद्ध में AI

चर्चा में क्यों?

भारत, सेना में मानव रहति लड़ाकू प्रणाली (UCS) को शामिल करने के अभियान पर है। अगस्त 2022 में इसने "स्वार्म ड्रोन" को अपने यंत्रिकृत बलों में शामिल किया, जो "फ्यूचर-प्रूफ" भारतीय नौसेना (IN) बनाने में स्वायत्त प्रणालियों के महत्त्व को दोहराता है।

- सशस्त्र संघर्ष में इनके बढ़ते उपयोग के बावजूद कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त मानव रहति युद्ध प्रणाली कानून, नैतिकता और उत्तरदायित्व के प्रश्न उठाती हैं।

मानव रहति युद्ध प्रणाली:

■ परिचय:

- मानव रहति युद्ध प्रणाली (UCS) भविष्य में युद्ध के नियमों को बदलने वाले नए युग के हथियार बनने जा रहे हैं तथा सैन्य शक्तियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- 21वीं सदी के इन तथाकथित प्रमुख हथियारों के लिये सामान्यतः कोई स्वीकृत परिभाषा नहीं है।
- अनुसंधान के अनुसार, **UCS एक एकीकृत युद्ध प्रणाली है जिसमें मानव रहति लड़ाकू प्लेटफॉर्म, टास्क पेलोड, कमांड और कंट्रोल (C2) सिस्टम तथा नेटवर्क सिस्टम शामिल हैं।**
- क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिये उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है,
 - डीप स्पेस मानव रहति प्रणाली
 - मानव रहति हवाई वाहन प्रणाली
 - स्थल मानव रहति प्रणाली
 - भूतल मानव रहति प्रणाली
 - जल के नीचे मानव रहति प्रणाली

■ महत्त्व:

- तेज़ी से जटिल अंतरराष्ट्रीय स्थिति और क्रूर सैन्य युद्धों का सामना करने में लड़ाकू सैनिकों के जीवन और सुरक्षा को बहुत खतरा होता है।
- इस समय मानव रहति लड़ाकू प्रणाली तेज़ी से महत्त्वपूर्ण होती जा रही है तथा धीरे-धीरे युद्ध के मैदान पर एक महत्त्वपूर्ण हमला और रक्षा बल बन गई है।
- स्थल मानव रहति प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मानव रहति भागीदारी के आधार पर कुछ हथियारों और उपकरणों को ले जा सकती है तथा टोही, निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप एवं प्रत्यक्ष मुकाबला करने के लिये कॉन्फिगर किया गए वायरलेस संचार उपकरणों के माध्यम से इसे दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।
- UCS (Unmanned Combat Systems) में **स्वचालन की उच्च क्षमता, बेहतर रिमोट नियंत्रण, आधुनिक डिजिटल संचार क्षमता, लक्ष्य का पता लगाने और पहचान करने की उत्कृष्ट क्षमता, बेहतर बचाव तथा ज़मीनी वातावरण के लिये मज़बूत अनुकूलन क्षमता** है।

AI वारफेयर द्वारा उठाई गई नैतिक चर्चाएँ:

■ साझा देयता का जोखिम:

- AI युद्ध नेटवर्क प्रणालियों के बीच साझा दोष के अवसरों में वृद्धि करता है, खासकर जब **हथियार एल्गोरिदम बाहरी स्रोतों से प्राप्त होते हैं और उपग्रह एवं लक्ष्य सिस्टम** जो युद्ध समाधान को संक्षम करते हैं, उपयोगकर्ता के नियंत्रण में नहीं होते हैं।

■ आत्मविश्वास की कमी:

- AI में कुछ विशेष प्रकार के डेटा की पहचान करने की विशेषता है। डेटा के संग्रह में डेटा विश्लेषण के लिये निर्देशों के सेट और संभावित परिणामों के चयन में तर्कसंगत निर्णय लेने में गड़बड़ी होने पर AI तकनीक में में विश्वास कम हो जाता है।

■ युद्ध के नियमों के साथ असंगत:

- AI हथियार प्रणालियों को उन तरीकों से स्वचालित कर सकता है जो **युद्ध के नियमों के साथ असंगत हैं।**

■ परिणामों की सूचना:

- कंप्यूटर संभाव्य आकलन के आधार पर मनुष्यों को लक्षित करने की एक प्रणाली है जो केवल मशीन से सीखे अनुभवों पर कार्य करती है। **कंप्यूटर के पास एक निर्धारित निर्णय लेने के लिये न तो सभी प्रासंगिक डेटा की उपलब्धता है और न ही यह पहचानता है कि इष्टतम समाधान को प्राप्त करने हेतु उसे कतिनी जानकारी की आवश्यकता है।**
- यदि इसने युद्ध/संघर्ष में गलत तरीके से बल का प्रयोग किया है, तो **किसी को जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि मशीन पर दोष नहीं लगाया जा सकता है।**

स्वार्म ड्रोन:

■ परिचय:

- स्वार्म ड्रोन छोटे और हल्के हवाई वाहनों का एक संग्रह है जिसे एक ही स्टेशन से नियंत्रित किया जा सकता है।
- ये ड्रोन **उन्नत संचार प्रणालियों से लैस हैं जो उन्हें समूहिक रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती हैं।**

- हमले और नगिरानी मोड के लिये वभिन्नि उड़ान संरचनाओं के नरिमाण के लिये **स्वार्म (swarm) ड्रोन संचार प्रणालियों** के माध्यम से **एक-दूसरे के साथ संपर्क भी कर सकते हैं।**
- ये ड्रोन वशिधी इकाई के खलिाफ एक संयुक्त हमले का समन्वय कर सकते हैं और एक ही मशिन पर कई तरह के पेलोड ले जा सकते हैं।
- स्वार्म/ड्रुंड ड्रोन AI सॉफ्टवेयर और स्वार्मगि एल्गोरदिम द्वारा संचालित होते हैं, जसिसेउनमें **मनुष्यों की न्यूनतम सहायता के साथ स्वायत्त रूप से कार्य करने की क्षमता होती है।**
 - अप्रत्याशति हमलों के मामले में AI प्रोग्राम का उपयोगलक्ष्यों की पहचान करने और प्रतिक्रिया को तीव्रता प्रदान करने के लिये भी कया जा सकता है।

■ लाभ:

- **हर मौसम में संचालन योग्य:** स्वार्म/ड्रुंड ड्रोन प्रणाली को अधिक ऊँचाई, खराब मौसम की स्थितिमें भी इस्तेमाल कया जा सकता है
- **उच्च गतिऔर चपलता:** ये ड्रोन उन्नत मोटरों द्वारा संचालित होते हैं और इनमें 100 कमी. प्रतिघंटे की गतिसे उड़ने की क्षमता होती है जो इसे सैन्य अभियानों के लिये उच्च गतिवि चपलता प्रदान करते हैं।
- **वभिन्नि प्रकार मशिनों के लिये नयिोजति:** ये सशस्त्र बलों द्वारा वभिन्नि प्रकार के आक्रामक और रक्षात्मक अभियानों के लिये तैनात कया जा सकते हैं क्योंकिवे टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, गोला-बारूद रखने वाले क्षेत्रों, ईंधन डंप और आतंकी लॉन्च पैड के खलिाफ हमला करने की क्षमता से पूर्ण हैं।
- **ATR की वशिषता:** स्वार्म ड्रोन आर्टफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हैं और स्वचालित लक्ष्य पहचान (Automatic Target Recognition- ATR) सुवधि से लैस हैं, जो उन्हें स्वचालित रूप से लक्ष्यों को पहचानने में सक्षम बनाता है। टैंकों, बंदूकों, वाहनों और मनुष्यों की पहचान करने तथा लक्ष्य भेदन संबंधी त्रुटि की संभावना को कम करने के लिये ऑपरेटरों की स्क्रीन पर जानकारी प्रदर्शति करने में सक्षम है।

आगे की राह

- सशस्त्र संघर्ष के सभी पक्षों को शत्रुता के दौरान सशस्त्र ड्रोन के किसी भी उपयोग को प्रासंगिक **अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून (International humanitarian law- IHL)** के सदिधांतों का पालन करना चाहयि।
- अतः यह सुनिश्चित करना चाहयि कि **उनके द्वारा उपयोग कयि जाने वाले किसी भी सशस्त्र ड्रोन से नागरिकों को कोई वशिष हानि न हो।**
- ड्रोन हमलों में पारदर्शति और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये पार्टयिों को ड्रोन के उपयोग को नयितरति करने वाली अपनी नीतयिों को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, **जसिमें यह भी शामिल है कि कैसे नागरिकों के नुकसान का आकलन और पीडितों का उपचार कया जाए।**
- सशस्त्र संघर्ष में शामिल सभी पक्षों जो IHL के अनुपालन से परे हैं, **पार्टयिों को नागरिकों के लिये सशस्त्र ड्रोन के उनके उपयोग के मानवीय प्रभाव पर वचार करने की आवश्यकता है, जसिमें नागरिक बुनयादी ढाँचे की क्षति और मानसकि स्वास्थ्य आघात भी शामिल है।**
- यह पहचानना महत्त्वपूर्ण है कि युद्ध में AI युद्ध प्रभावशीलता और नैतिकता दोनों का सवाल है। AI ने समुद्री मोर्चे पर मानव रहति ससि्टम को जोखिम में डाल दिया है, **जसिसे सेना को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नयिोजति करने की आवश्यकता होती है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिन्लखित गतिविधियिों पर वचार कीजयि: (2020)

1. खेत में फसल पर पीडकनाशी का छड़िकाव
2. सकरयि ज्वालामुखयिों के क्रेटरों का नरीक्षण
3. DNA वशि्लेषण के लिये उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना

तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपर्युक्त गतिविधियिों में से कसि ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक संपन्न कया जा सकता है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

